IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वैश्वीकरण के दौर में भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी की स्थिति

डॉ.गरिमा सिंह

सहायक प्राध्यापक–अर्थशास्त्र

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना ।

प्रस्तावना –

वैश्वीकरण के समर्थक विशेषकर विकसित देशों से वैश्वीकरण की परिभाषा को पहले तीन अंगो तक सीमित कर देते हैं अर्थात् निर्बाध व्यापार प्रवाह, निर्बाध पूंजी प्रवाह और निर्बाध टेक्नालॉजी प्रवाह, वे विकासशील देशों पर वैश्वीकरण की इस परिभाषा को स्वीकार करने के लिए दबाव डालते हैं और उनके द्वारा तय की गई परिधि में वैश्वीकरण के बारे में विचार–विमर्श करने पर बल दते हैं। परन्तु विकासशील देशों के बहुत से अर्थशास्त्री यह मत रखते है कि यह परिभाषा अपूर्ण है और यदि वैश्वीकरण के समर्थकों का अंतिम लक्ष्य समस्त संसार को एक (सार्वभौम ग्राम) के रूप में निर्बाध प्रवाह की उपेक्षा नहीं की जा सकती।'' वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसक द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, टेक्नालॉजी, पूंजी और मानवीय पूॅजी का भी निर्बाध प्रवाह हो सके। अर्थशास्त्रियां के अनुसार वैश्वीकरण के चार अंग है –

1) व्यापार अवरोधकों को कम करना ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं का बेरोक टोक आदान प्रदान हो सके।

2) ऐसी परिस्थिति कायम करना जिसमें विभिन्न राज्यों में पूंजी का स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो सके।

3) ऐसा वातावरण कायम करना कि टेक्नालॉजी का निर्बाध प्रवाह हो सके।

जनवरी 2016 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था स्वीकार किया गया है। 2015 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि 7.3 प्रतिशत रही है, जबकि 2016 व 2017 में 7.4–7.4 प्रतिशत की

वृद्धियाँ संभावित है। चीन में 2015 में वृद्धि 6.9 प्रतिशत रही है, जबकि 2016 में यह 6.3 प्रतिशत तथा 2017 में यह 6.0 प्रतिशत ही रहने की संभावना है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मेक्सिकों में वृद्धि दर 2015 में 2.5 प्रतिशत रही है, जबकि 2016 व 2017 में यह क्रमशः 2.6 प्रतिशत व 2.9 प्रतिशत लाभांवित है, ब्राजील में 2015 में वृद्धि 3.8 प्रतिशत रहने के पश्चात 2016 व 2017 में क्रमशः 3.5 प्रतिशत व शून्य संभावित है।

वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्रतर विकास की पर्याय सी बन गई है। उसकी वार्षिक विकास दर 7.2ः विदेशी मुद्रा भंडार दो सौ अरब डालर, बचत दर तीस प्रतिशत एवं मुंबई शेयर बाजार सूचकांक चौदह हजार के स्तर तक पहुँच चुका है। अरबपतियों की संख्या की दृष्टि से हम जापान को पीछे ही नहीं छोड़ चुके हैं बल्कि प्रति वर्ष सर्वाधिक अरबपति हमारे यहाँ ही बन रहे हैं। अमेरिका जैसे देश भारत को आर्थिक शक्ति मानकर आंतकित से हो रहे हैं। भारतीय कंपनियाँ अपने से कई गुना बड़ी विदेशी कंपनियों को तेजी से अधिगृहीत करने में लगी हं, विदेशी शेयर बाजारों में ऐसी कंपनियों पर भारी होती जा रही हैं, भारतीय प्रबंधकों को हर तरफ मांगा जा रहा है और विदेशी, भारत में पूँजी लगाने के लिए पंक्तिबद्ध हो रहे हं।

दूसरी ओर भारत में गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, असमानता, शोषण, अनुत्पादकता बिजली व पानी की कमी, लिंग भेद निम्नतर जीवन स्तर आदि समस्याओं के हल के संकेत तक नहीं मिल रहे हैं। इन सबसे हमारा, सामाजिक तानाबाना भी बिखरने लगा है। क्योंकि भारतीय '' इंडिया '' और 'भारत' में बंट कर रह गये हं, ऐसे में स्वाभाविक प्रश्न यह ही उठते है कि वैश्वीकरण में भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी, कैसे व क्यों प्रभावित हो रही है? तथा इससे भारतीयों का भविष्य कितना बन या बिगड़ सकता है।''

''वैश्वीकरण के उद्देश्यों की रूपरेखा देते हुए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। हमारी मुख्य चिंता यह है कि वैश्वीकरण से सभी देशों को लाभ प्राप्त होना चाहिए और सारी दुनिया में सभी लोगों के कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि इसमें गरीब देशों की आर्थिक वृद्धि की दर में उन्नति होनी चाहिए और विश्व निर्धनता कम होनी चाहिए।

वैश्वीकरण ने विश्व के गरीब वर्गों के हितों के लिए कार्य नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न देशों में पारस्परिक असमानताएँ बढ़ी है और देशों के भीतर भी इसमें वृद्धि हुई है, न यह पर्यावरण के पोषण के लिए कार्य कर रहा है। साम्यवाद से बाजार अर्थव्यवस्था या अत्यधिक विनियमित राज्य से बाजार अर्थव्यवस्था की ओर संक्रान्ति इतने बुरे ढंग से व्यवस्थित की गयी कि चीन, वियतनाम और पूर्वीय यूरोप के कुछ राज्यों को छोड कर इनमें गरीबी में वृद्धि हुई है। दोष वैश्वीकरण में नहीं है परन्तु उस ढंग में है जिससे इसकी व्यवस्था की गयी। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस परिस्थिति का निचोड़ इन शब्दों में व्यक्त किया गया है : ' अर्थव्यवस्था अधिकाधिक वैश्वीकृत बन रही है, जबकि सामाजिक और राजनैतिक संस्थान मोटे तौर पर स्थानीय, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ही रहे हैं।''

''वैश्वीकरण के अधीन समष्टि आर्थिक नीति विकास की दरों को त्वरित करने पर बल देती रही है और यह मान्यता की गयी कि रोजगार–जनन अपन आप विकास के फलस्वरूप बढ़ जाएगा लेकिन ऐसी नहीं हुआ। जब 1993–94 से 1999–2000 के दौरान सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि–दर 6 प्रतिशत हो गयी, तब रोजगार जनन एकदम गिरकर 1.0ः के स्तर पर आ गया। 1983 से 1993–94 की दस वर्षीय अवधि के दौरान सापेक्षतः कम जी.डी.पी. वृद्धि के साथ रोजगार वृद्धि दर 20 प्रतिशत प्रति वर्ष रही। उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद के काल में सार्वजनिक क्षेत्र में स्वैच्छिक निवृत्ति और आकार–संकुचन के कारण रोजगार का विस्तार सीमित हो गया, परन्तु निजी क्षेत्र का निवेश इस रिक्ति को भर नहीं पाया। परिणामतः कुल रोजगार की वृद्धि दर पर दुष्प्रभाव पड़ा।''

'' भारत में खुली बेरोजगारी बहुत कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या अल्परोजगार है। 7.32ः की कुल बेरोजगारी में खुली बेरोजगारी केवल 2.8ः थी, जबकि अल्प रोजगार की मात्रा 4.51ः थी। यह बहुत जरूरी है कि बेरोजगारों तथा श्रम शक्ति में नव प्रवेशकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और इसके लिए रोजार रणनीति को विकास रणनीति के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। अल्प रोजगारों का अधिकतर भाग, विशेषकर वे जो अत्यधिक रूप में अल्प रोजगार प्राप्त है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे है। रोजगार जनन कार्यक्रम जैसे जवाहर रोजगार याजना और प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना से अल्परोजगार को कम करने में सहायता मिलती है। इस दृष्टि से ये प्रोग्राम गरीबी को कम करने में कार्यभाग अदा करते है और इन प्रोग्रामों को बेहतर रूप में लक्षित किया जाए ताकि गरीब लोगों की सही रूप में सहायता हो सके।''

वैश्वीकरण से मानव के सोच में परिवर्तन आया है तथा बालक–बालिका के बीच मतभेद में कमी आई है। आज का भारतीय समाज बालिकाओं को काफी महत्व देने लगा है और जो बालिकायें पहले बोझ मानी जाती थी, आज उनके जन्म पर जन्मोत्सव मनाया जाता है। वैश्वीकरण ने काफी हद तक समानता स्थापित की है। ''दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और यह बदलाव कई दिशाओं में हो रहा है। पढ़ लिखकर विकास की दौड़ में आ खड़ी हुई महिलाएं अब घर की चार दीवारियों से निकल के कामकाजी की दुनिया में शामिल हो रही है। बदली हुई सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर आसानी से मिलने लगे है जिस कारण उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, समाज में स्वयं अर्जित प्रतिष्ठा पाने के साधन मिले और मिली है जीवन को अपने तरीके से जीने की आजादी।

निष्कर्ष –

उचित वैश्वोकरण के नीति संबंधी ढांचे का स्वरूप बताया गया है। जिसके द्वारा विकास रोजगार और समानता के लक्ष्यों को समन्वित किया जाना चाहिए। अच्छे काम का लक्ष्य वैश्वीकरण के युग में केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है। यदि वैश्वीकरण के श्रम पर पड़ने

वाले दुष्प्रभाव कम किए जा सके और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक आधारसंरचना के निर्माण के सार्वजनिक कार्यक्रमों को मजबूत बनाया जाए। इन प्रोग्रामों को विशेष रूप में कृषि वृद्धि दरों को उन्नत करने के लिए लक्षित करना होगा। क्योंकि विकसित देशों के किसानों को प्राप्त उच्च स्तर के सब्सिडियों के कारण देश के किसान दुष्प्रभावित हुए है। वैश्वीकरण का अल्पविकसित और सबसे कम विकसित देशों पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। इसने समृद्ध और शक्तिशाली देशों को लाभ पहुंचाया है। जरूरत इस बात की है इसके मार्ग में परिवर्तन किया जाए ताकि यह अधिक समावेशी बना जाए और समाज के हाशिये पर धकेले गए वर्गों को अपनी छत्रछाया में ला सके। वास्तव में उचित वैश्वीकरण विकास और रोजगार प्रोन्नत करने में सहायक हो सकता है।

सुझाव –

1. अच्छा राजनैतिक प्रशासन जो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली पर आधारित हो।
2. एक प्रभावी राज्य स्थापित होना चाहिए। जो उच्च आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सके, सामाजिक वस्तुएं और सामाजिक संरक्षण उपलब्ध करा सके।
3. लाभपूर्ण सामाजिक बातचीत के लिए श्रमिकों एवं नियोजकों के सशक्त प्रतिनिधित्व वाली संस्थाएँ होनी भी अनिवार्य है।
4. सबसे अधिक प्राथमिकता ऐसी नीतियों को देनी होगी जो पुरूषों एवं स्त्रियों के लिए (समुचित रोजगार) की केन्द्रीय आकांक्षा को पूरा कर सके, इन अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की उत्पादिता को ऊपर उठा सके और उपक्रमों एवं अर्थव्यवस्थाओं की प्रतियोगिता शक्ति को बढ़ा सके। अभी तक वैश्वीकरण ने अधिकाधिक वैश्विक अर्थव्यवस्था कायम करने में सहायता दी है।'

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था मान चन्द्र खंडेला प्रकाशक– प्रेमचन्द्र बाकलीवाल अधिकार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स 2014
2. दत्र एवं सुन्दरम – भारतीय अर्थव्यवस्था एस.चन्द एण्ड कंपनी प्रा. लि. रामनगर नई दिल्ली 2008
3. कृषि अर्थशास्त्र – डॉ. एस.लसी. जैन, डॉ. पी.डी. माहेश्वरी, प्रकाशक– कैलाश पुस्तक भवन हमीदिया मार्ग भोपाल
4- www.google.com
5- www. yahoo.com
6. प्रतियोगिता दर्पण (सामान्य अध्ययन) – भारतीय अर्थशास्त्र 2016–17
7. कुरूक्षेत्र ग्रामीण विकास को समर्पित नवम्बर 2016